

# गुजरात विधानसभा में मंत्री कनू देसाई ने की अहमदाबाद मेट्रो फेज-3 की घोषणा थलतेज से गोधावी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम से एयरपोर्ट तक विस्तार

**शहरी विकास की  
33504 करोड़ की  
बजट मांगें पारित**

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com

गांधीनगर. गुजरात विधानसभा में शहरी विकास एवं गृह निर्माण विभाग की 33,504 करोड़ रुपए की बजट मांगें पारित कर दी गईं। यह बजट गुजरात के शहरी विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। शहरी विकास एवं गृह निर्माण मंत्री कनू देसाई ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुजरात की 48 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है, इसलिए बजट का बड़ा हिस्सा शहरी योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो फेज-3 की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके तहत थलतेज से गोधावी और मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम से सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए 58.53 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक का विस्तार किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 2217.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।



**मुख्यमंत्री नगर नवजीवन योजना और पुनर्विकास :** उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री नगर नवजीवन योजना के अंतर्गत पुराने इलाकों का कायाकल्प करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। योजना के तहत ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के जरिए आर्थिक अवसर सृजित होंगे और चयनित क्षेत्रों में इनेज, जलापूर्ति और सड़कों का सुधार किया जाएगा। शहरों में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नमो स्वदेशी अर्बन मॉल्स और मेलों के लिए 45 करोड़ रुपए और फेरीवालों के लिए 43 स्थानों पर आधुनिक मार्केट के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

**कॉमनवेलथ गेम्स, ओलंपिक आयोजनों के लिए 10 करोड़:** उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को आगामी कॉमनवेलथ गेम्स और ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मोटेरा, नवरंगपुरा और हीरावाड़ी जैसे प्रमुख खेल स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। प्रत्येक महानगरपालिका में पेशेवर खेल सुविधाएं विकसित करने और फ्लाइओवर के नीचे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

**नमो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना**

शहरों में रहने वाले गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराए के मकान उपलब्ध कराने हेतु 'नमो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना' लागू की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में अहमदाबाद और सूरत में पायलट प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी संपत्तियों के रखरखाव के लिए 'जीवन धारा' योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन डेली वाटर सप्लाई के तहत 62 नगरपालिकाओं में रोजाना पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

**सैटेलाइट टाउन और पर्यटन विकास**

कलोल, साणंद, सावली, बारडोली और हीरासर को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। लोथल में थीम पार्क और तीर्थधाम अंबाजी के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।